

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

संख्या २१२४ / एस०टी०डी०एम०/ २०११-१२

दिनांक मार्च २९, २०१२

- उप जिला मजिस्ट्रेट, कर्वी/मऊ।
- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चित्रकूट।
- क्षेत्राधिकारी, नगर, राजापुर एवं मऊ।
- खान निरीक्षक, चित्रकूट।

अधोहस्ताक्षरी को समाचार पत्रों एवं अन्य स्रोतों से इस आशय की काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि बालू/मोरम का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की क्षति हो रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में संलग्न विवरण के अनुसार वर्तमान समय में बालू/मोरम के ०६ खनन परमिट एवं ०१ खनन पट्टा चल रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद में यदि कहीं पर बालू/मोरम का खनन किया जाता है, तो वह पूर्णतया अवैध खनन है।

२— यह भी अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में संलग्न विवरण के अनुसार खनिज सचल जौच दल/रवन्ना संग्रह के मात्र ०३ केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद में अन्य कहीं भी रवन्ना संग्रह केन्द्र संचालित है, तो वह पूर्णतया अवैध है।

३— उक्त के अतिरिक्त विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या—१९६२८—१९६२९ वर्ष २००९, दीपक कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २७.०२.२०१२ (छायाप्रति संलग्न) के कार्यकारी अंश का भी अवलोकन करें, जिसके अनुसार ०५ हेठो से कम क्षेत्र में भी खनन कार्य हेतु पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने—अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सतर्क दृष्टि रखते हुए अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगायें तथा अवैध खनन पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्नक:— १. बालू/मोरम के खनन परमिट/पट्टे की सूची।

२. खनिज सचल जौच दल/रवन्ना संग्रह केन्द्रों की सूची

३. मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २७.०२.२०१२ की छायापति

(डॉ आदर्श सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

- प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु अपने स्तर से समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि अपर जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अवैध खनन की शिकायत मोबाइल नं०—९४५३९५८९४१ (खान निरीक्षक), ०५१९८—२३५३०५ एवं ०५१९८—२३५४२५ पर दिये जाने हेतु सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये।

(डॉ आदर्श सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट

जनपद चित्रकूट में कार्यरत बालू/मोरम के परमिट का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	खसरा नं०	स्क्रीफल है०	खनिज का नाम	पट्टे की अवधि
					कब से कब तक
1	कर्वी दहिनी	8021	11.20	बालू/मोरम श्री जगन्नाथ	06.01.12 05.04.12
2	कर्वी डिघरी	04	5.24	बालू/मोरम श्री सन्तोष कुमार पाण्डे	04.01.12 03.04.12
3	कर्वी कहेटामाफी	92/2	12.01	बालू/मोरम श्री अरविन्द कुमार मिश्रा	09.02.12 08.05.12
4	कर्वी लग्नियारी	2मि०	3.33	बालू/मोरम श्री सुरेन्द्र कुमार	04.02.12 03.05.12
5	कर्वी वीरधुमाइ	02	0.43	बालू/मोरम श्री वीरभान सिंह	05.03.12 04.06.12
6	कर्वी गड्ढोली	21	5.67	बालू/मोरम श्री उमाकान्त त्रिपाठी	05.03.12 04.06.12

जनपद चित्रकूट में कार्यरत बालू/मोरम के पट्टों का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	खसरा नं०	स्क्रीफल है०	खनिज का नाम	पट्टे की अवधि
				कब से कब तक	
1	कर्वी पिलखिनी	04	03.24	बालू/मोरम श्री धनश्याम सिंह(नवी०)	17.12.11 16.12.14 बालू है

जनपद—चित्रकूट में कार्यरत सचल जाँच दल/रवना संग्रह केन्द्र का विवरण

क्र०सं०	तहसील का नाम	स्थल का नाम	प्रभारी कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	2	3	4	5
1	कर्वी	शिवरामपुर	श्याम कुमार श्रीवास्तव	डिल मैकेनिक
2	कर्वी	कालूपुर	कपिल देव	खनिज सहायक
3	मऊ	मुर्का	कपिल देव	खनिज सहायक

खान निरीक्षक
चित्रकूट

10070

२०-३/१२

सर्वोच्च प्राप्तिकर्ता

मांग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश।

संख्या-५८१/८६-२०१२-२३५/२०१०

प्रेषक

मुकेश कुमार गुप्ता
विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुपालन

लखनऊ दिनांक २२ भाद्र, २०१२

विषय: आई०८० सं०-१२-१३ /२०११, विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-
१८८२४ -१८८२९ वर्ष २००९, दीपक चूमार व अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त अन्य में पारित मांग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2012 के अनुपालन के संबंध में।

विभिन्न विधिवारी

महोदय

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिका में मांग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2012 के कार्यकारी ओरा निम्नलिखित हैं:-

जिला।/धर्मार्थ

महोदय

२५/३/१२

"We, in the meanwhile, order that leases of minor mineral including their renewal for an area of less than five hectares be granted by the States/Union Territories only after getting environmental clearance from the MoEF. Ordered accordingly."

अतः कृपया मांग सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०८० लखनऊ के माध्यम से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार गुप्ता)

विशेष सचिव।

संख्या- (१) /८६-२०१२, इसी दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु भेजिये:-

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०८०, लखनऊ।

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

गार्ड बुक।

आङ्गा से,

(मुकेश कुमार गुप्ता)

विशेष सचिव।

Subram 235-2010

985

24/03/12
21.03.12